वर्ष-14 - अंक 90
पृष्ट-04 मूल्य : 01 रुपया

सीतापुर
गुरुवार ,09 जुलाई 2026

RNI.No. UHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

swatantraprabhat.com

epaper.swatantraprabhat.com

जो लिखेगा, वही टिकेगा

लखनऊ से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून गाज़ियाबाद , दिल्ली ,पंजाब , हरियाणा ,चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

अमीनाबाद इंटर कॉलेज में बेटियों की शिक्षा का नया अध्याय शुरू 3 | सीरिया दौरे पर थे मैक्रों, तभी दमिश्क में धमाकों से दहला इलाका 4 | आस्था की सुरक्षा के लिए नई चुनौती 02

'सिर्फ 8 लोग शामिल, पूरे ट्रस्ट को बदनाम करना गलत- CM योगी

सरकार और ट्रस्ट पर निशाना साध रहे लोगों पर सीएम योगी जमकर बरसे

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरे भारत के आस्था को आहत करने, प्रहार करने का ठेका ले लिया है

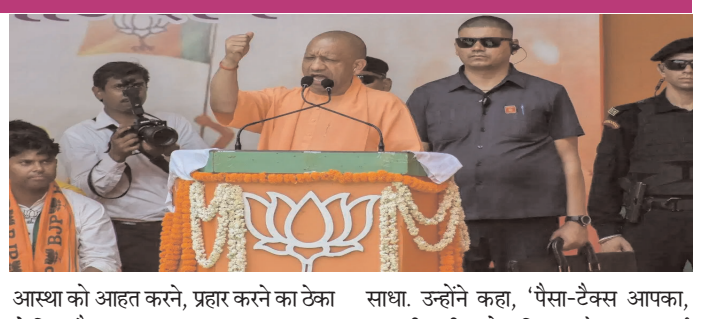

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बुधवार को कहा कि लगभग 150 लोग अयोध्या मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग में हैं. ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें कुछ जानकारी मिली कि चढ़ावे के पैसे में चोरी हो रही है, एसआईटी गठित की जानी चाहिए. सीएम ने कहा कि हमने एक एसआईटी गठित की, जांच किया और प्रमाण मिला कि सिर्फ 6 लोग इसमें चोरी करते पाए गए और दो लोग इसमें साजिश का पार्ट थे यानी कुल 8 लोग इसमें शामिल थे दरअसल, सीएम योगी चित्रकूट में 950 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को दी, ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई. फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरे अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्रीराम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से आता है. लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरे भारत के आस्था को आहत करने, प्रहार करने का ठेका ले लिया है'.

समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 'आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं. राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है. जब ये लोग विरासत का सम्मान नहीं कर सकते तो विकास कैसे करेंगे. देख सपाई बिटिया घबराई, सपा की ये पहचान बन गई थी. जो जन्मजात अयोध्या को कोसते थे, उनको एक मुद्दा मिल गया. पहले कहते थे कि राम काल्पनिक हैं. राम और कृष्ण काल्पनिक हैं, तो अयोध्या, चित्रकूट क्या है...बरसाना, पंचवटी क्या है. हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलते हैं. राम और अयोध्या को बदनाम करने का ठेका सपा-कांग्रेस ने ले लिया है'

वक्फ पर भी साधा निशाना

सीएम ने वक्फ को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'पैसा-टैक्स आपका, आपकी जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करा देते थे. वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड कब्जा ली. वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड बेच दी गई. ये सीधे-सीधे डकैती थी. इन लोगों के दोहरे चरित्र को देखकर गिरगिट भी शरमा रहा होगा'

क्या है राजनीतिक संदेश?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी सरकार दो समानांतर संदेश देने की कोशिश कर रही है. पहला, भ्रष्टाचार या चढ़ावे की चोरी में शामिल किसी भी शख?स को बख्शा नहीं जाएगा. गिरफ्तारियां और एसआईटी जांच इसी संदेश का हिस्सा हैं. दूसरा यह कि सरकार यह भी साफ करना चाहती है कि कुछ व्यक्तियों पर लगे आरोपों के आधार पर पूरे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट या राम मंदिर निर्माण अभियान की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए.

इस्लाम अपनाने वालों के आरक्षण पर SC पहुंची तमिलनाडु सरकार

हाईकोर्ट बेंच ने अपने फैसले में माना कि यह सरकारी आदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायिक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

तमिलनाडु में इस्लाम अपनाने वालों के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आरक्षण रद्द करने के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने 2024 में जारी सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले कहा था कि इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता. हाईकोर्ट ने 2024 में जारी एक सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस आदेश में पिछड़े वर्गों (बी सी), अति पिछड़े वर्गों (एमबीसी), विमुक्त समुदायों या अनुसूचित जातियों से इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) मानने और आरक्षण का लाभ लेने के लिए 7 अधिसूचित समुदायों में से किसी एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी गई थी।

इन 7 मुसलमानों को आरक्षण का लाभ

'तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993' के तहत पिछड़ा वर्ग मुस्लिम के रूप में अधिसूचित मुसलमानों के 7 समुदाय- अंसार, दक्कनी मुसलमान, दुबेकुला, लब्बाई (जिसमें रौथर और मरकयार शामिल हैं), माप्पिला, शेख और सैयद आते हैं जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पीबी बालाजी की हाईकोर्ट बेंच ने अपने फैसले में माना कि यह सरकारी आदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायिक फैसलों के बिल्कुल खिलाफ था, जिनमें कहा गया है कि इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को केवल मुस्लिम ही माना जा सकता है।

2015 में इस्लाम ग्रहण कर लिया

हाईकोर्ट समीर अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने 2015 में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था. इसके लिए 2016 में एक गजट नोटिफिकेशन (सरकारी आदेश) जारी किया गया था. समीर ने इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार शादी भी की और इस शादी से उसके 2 बच्चे हुए. इसी दौरान, समीर ने खुद को 'मुस्लिम लब्बाई' समुदाय का सदस्य बताने वाला सामुदायिक प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन किया।

लेकिन तहसीलदार ने इस आवेदन खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी. समीर की ओर से दावा किया गया कि बीसी, एमबीसी और एमडब्ल्यू विभाग की ओर से 9 मार्च, 2024 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

'मनमाने ढंग से आदेश जारी नहीं'

सरकारी आदेश को देखने के बाद बेंच की राय थी कि यह न्यायिक जांच में शायद टिक न पाए. इसलिए इस बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकारी आदेश की वैधता की जांच के लिए राज्य को एक पक्ष के रूप में शामिल कर लिया. राज्य ने तर्क दिया कि सरकारी आदेश मनमाने ढंग से जारी नहीं किया गया था.

सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने 6 फरवरी, 2024 के पत्र के जरिए सरकार से सिफारिश की थी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, 7 पहचाने गए समूहों में से किसी एक में धर्म परिवर्तन करने पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिया जाए।

साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यह सरकारी आदेश विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही जारी किया गया था. यह आदेश इसलिए भी जारी किया गया ताकि जो लोग पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा रहे थे, वे इस्लाम में धर्म परिवर्तन के कारण इसे न खो दें. इस तरह राज्य ने तर्क दिया कि ऐसे लोगों को आरक्षण देने से सामाजिक संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है. फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर की है. राज्य की यह याचिका एडवोकेट बी. करुणाकरण (एओआर) के जरिए दायर की गई है।

संक्षिप्त ख़बरें

चंद्रभानु गुप्त महाविद्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि

सीतापुर 8 जुलाई बक्शी का तालाब स्थित चंद्रभान गुप्त महाविद्यालय में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ. टीपी सिंह, पूर्व प्राचार्य डॉ. आरके कुशवाहा एवं प्राचार्य डॉ. योगेंद्र कुमार सिंह द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ. टीपी सिंह ने बताया कि 'चंद्रशेखर जी भारतीय राजनीति में अपनी सादगी, निर्भीक नेतृत्व और समाजवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। 'मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस अवसर पर मृदा विज्ञान विभाग के आचार्य डॉ हृदय नारायण तिवारी, डॉ एस सी चंदा, डॉ जसकरन सिंह, डॉ सुधाकर सिंह, धनेंद्र कुमार सिंह, धीरेंद्र कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी शिवमंगल चौरसिया, डॉ उपमा त्रिपाठी, डॉ अनिल कुमार वर्मा, इबाद खान सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए 17 जुलाई को लगेगा मोबाइल कोर्ट

प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा ने समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि 17 जुलाई को पूर्वान्ह 10 बजे से अफीम कोठी प्रतापगढ़ में न्यायालय/राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजनो के हितार्थ मोबाईल कोर्ट दिव्यांग न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में जनपद के समस्त विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहेगें। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन उपस्थित होकर अपनी शिकायतो समस्याओं का निराकरण करा सकते है।

सुमरावा में कचरे का ढेर: स्वच्छ भारत मिशन को मिल रही बड़ी चुनौती

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
सकरन संवाददाता नितिन कुमार

विकास खंड सकरन की सुमरावा ग्राम पंचायत के चौराहे पर लगा कचरे का विशाल ढेर स्वच्छ भारत मिशन की साख पर सवालिया निशान लगा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, यहां स्थित डस्टबिन कचरे से लबालब भरे हुए हैं और अतिरिक्त कचरा चारों ओर बिखरा पड़ा है, जिससे नालियां पूरी तरह जाम हो चुकी हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सफाई कर्मी केवल कागजों पर ही मौजूद हैं। वास्तविक सफाई का कोई निशान नहीं दिख रहा है। नालियों में जमा गंदे पानी में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं, जिससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्लास्टिक की पन्नियां, कागज और अन्य कचरा हवा में उड़कर आस-पास के घरों की रसोइयों तक पहुंच रहा है। चौराहे पर बिकने वाली खाने-पीने की चीजें और घरों में रखा भोजन दूषित हो रहा है।

ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, 'यह सिस्टम की नाकामी का बेहतरीन उदाहरण है। अगर समय रहते सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो पूरा गांव बीमारियों की चपेट में आ जाएगा।' ग्रामवासियों की मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने लापरवाह सफाई कर्मियों को हटाकर जिम्मेदार लोगों को तैनात करने की मांग की है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को खुले में शौच मुक्त और कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सुमरावा का यह हाल इस मिशन की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। ग्राम पंचायत और विकास खंड अधिकारियों से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की अपेक्षा की जा रही है, ताकि गांव स्वच्छता के लक्ष्य की ओर बढ़ सके। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग तुरंत हस्तक्षेप करें और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें, जिससे अन्य गांवों में भी ऐसी लापरवाही न हो।

4 साल तक जोड़े 10 के सिक्के, फिर बिना EMI खरीद ली 1.10 लाख की नई बाइक

शोरूम में सिक्कों को गिनने में दो घंटे लगे. यह घटना छोटी बचत की शक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व का प्रेरणादायक उदाहरण है.

तेलंगाना के नलगोंडा जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी वर्षों की बचत से बिना किसी ईएमआई या कर्ज के नई बाइक खरीदकर सभी को हैरान कर दिया. खास बात यह रही कि उसने बाइक की पूरी कीमत 10-10 रुपये के सिक्कों में चुकाई. शोरूम में जब सिक्कों से भरे बैग पहुंचे तो कर्मचारी भी हैरान रह गए और उन्हें रकम गिनने में करीब दो घंटे का समय लगा।

यह मामला नलगोंडा जिले के चिट्याला मंडल के वेलिमिनेडु गांव का है. यहां रहने वाले कोंडे रघुपति पिछले चार से पांच वर्षों से 10 रुपये के सिक्के अलग-अलग जमा कर रहे थे. उनका सपना था कि एक दिन इन्हीं छोटी-छोटी बचतों से नई मोटरसाइकिल खरीदेंगे.रघुपति के अनुसार, जब उनकी पुरानी स्प्लेंडर प्लस बाइक ने अचानक काम करना बंद कर दिया, तब उन्होंने नई बाइक खरीदने का फैसला किया. इसके बाद वह सीधे श्री विनायक मोटर्स के शोरूम पहुंचे और अपने साथ वर्षों से जमा किए गए सिक्कों के बैग लेकर पहुंचे।

पांच साल तक जोड़े 10-10 रुपए

शोरूम कर्मचारियों के सामने जब रघुपति ने बताया कि वह बाइक की पूरी कीमत सिक्कों में चुकाना चाहते हैं, तो पहले सभी चौंक गए. हालांकि, सिक्के भारतीय मुद्रा होने के कारण शोरूम ने भुगतान स्वीकार कर लिया. इसके बाद कर्मचारियों ने करीब दो घंटे तक बैठकर एक-एक सिक्का गिना. गिनती पूरी होने पर कुल राशि 1 लाख 10 हजार रुपये निकली, जिसके बाद रघुपति को नई स्प्लेंडर प्लस बाइक सौंप दी गई इस अनोखे लेनदेन को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जुट गई. कई लोगों ने इस पल का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग रघुपति की बचत की आदत और बिना कर्ज के बाइक

खरीदने के फैसले की सराहना कर रहे हैं।

छोटी बचत से रघुपति ने जोड़े 1 लाख 10 हजार रुपये

रघुपति ने कहा कि उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि उन्होंने किसी बैंक से लोन नहीं लिया और न ही किसी ईएमआई का सहारा लिया. छोटी-छोटी बचत के जरिए उन्होंने अपना सपना पूरा किया. यह घटना एक बार फिर यह संदेश देती है कि नियमित बचत, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, समय के साथ बड़ी पूंजी में बदल सकती है. रघुपति की अनोखी खरीदारी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

खैराबाद के भूमिजा आडिटोरियम में मुख्य मंत्री कैशलेश चिकित्सा समारोह के भव्य कार्यक्रम का सफल आयोजन

शासन की सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम सदस्य तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है ज़िला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर

खैराबाद सीतापुर माननीय मुख्य मंत्री कैशलेश चिकित्सा समारोह का सीधा प्रसारण में उपस्थित होने के लिए स्थानीय भूमिका बहुउद्देशीय हाल में बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के द्वारा संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के लगभग एक हजार शिक्षकों, शिक्षा मित्र अनुदेशकों एस आर जी ए आर पी संकुल शिक्षकों ने प्रतिभाग किया गया इस अवसर पर खैराबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर की बच्चियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन पर कैशलेश चिकित्सा से लाभान्वित होने वाले लगभग दो दर्जन शिक्षकों को लाभार्थी कार्ड वितरित किए गए।इस अवसर पर ज़िला अधिकारी डॉ राजा गणपति आर, मुख्य विकास अधिकारी,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, रेउसा विधायक ज्ञान तिवारी, एम एल सी शिक्षक इंजीनियर अवनीश पटेल, पवन कुमार सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला, ज़िला विद्यालय निरीक्षक, ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल, खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, खैराबाद उपस्थित रहे जबकि कार्यक्रम का सफ़ल संचालन ज़िला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, बेसिक शिक्षक संघ प्राथमिक रवीन्द्र दीक्षित, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ अध्यक्ष रामचंद्र मिश्र, प्रांतीय प्रवक्ता मनीष पांडेय डी सी प्रशिक्षण, आदि मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको कैशलेश चिकित्सा की सौगात देकर बहुत बड़ा काम किया है इसके लिया हम हृदय से उन्हें बधाई देना चाहते हैं और आपसे यानी शिक्षकों से निवेदन है कि आप अपने विद्यालय के मासूम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में कोई कसर न छोड़ें और जो आज डी बी टी की धनराशि खातों में भेजी गई है उसका सही उपयोग करवा दीजिए इसके लिए अभिभावकों से भी सम्पर्क कर लें साथ में यह भी कहा कि शिक्षकों के साथ साथ हम सभी का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। एम एल सी पवन सिंह चौहान और इंजीनियर अवनीश पटेल ने भी मुख्यमंत्री के इस कार्य की भरपूर सराहना की जबकि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा निर्धनों, शिक्षकों, चिकित्सकों व्यापारियों के हित की बात करते हैं इसी लिए यह कार्य किया साथ ही भारतीय स्टेट बैंक से जो सुविधाएं शिक्षकों को मिलने का समझौता हुआ वो भी अपने आप में अतुलनीय है इस लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं जबकि ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक सभी आगंतुकों का स्वागत सत्कार और शिक्षकों से मेल मिलाप करते रहे मुख्य विकास अधिकारी सभी को उचित निर्देशन प्रदान करती रहीं अंत में ज़िला अधिकारी डॉ राजा गणपति आर ने आभार व्यक्त करते हुए शासन को अवगत कराते हुए पूर्णतया आश्वस्त कराया कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के आख़िरी व्यक्त तक पहुंचाने में ज़िला प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है।

KMCLU के 11वें दीक्षांत समारोह में मां-बेटी सम्मेलन का आयोजन

लखनऊ। ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय (KMCLU) के 11वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित 'मां-बेटी सम्मेलन' में छात्राओं और उनकी माताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बालिकाओं की उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा माताओं को बेटियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। सम्मेलन के दौरान छात्राओं और उनकी माताओं से सीधा संवाद किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के महत्व, करियर निर्माण, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और भविष्य की चुनौतियों जैसे विषयों पर चर्चा हुई। छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए, जबकि माताओं ने बेटियों की शिक्षा में परिवार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में डॉ. इला पांडे (एमडी, इंटरनल मेडिसिन) ने छात्र-छात्राओं की मेडिकल काउंसलिंग करते हुए स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार तथा नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी।

1,246 विद्यार्थियों को मिली उपाधियां

दीक्षांत समारोह के बाद विश्वविद्यालय के प्रो. शौबान सईद ने बताया कि इस वर्ष 799 स्नातक (यूजी), 437 स्नातकोत्तर (पीजी) तथा 10 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। कुल उपाधि प्राप्त करने वालों में 495 छात्राएं और 751 छात्र शामिल रहे। उन्होंने बताया कि 939 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 120 विद्यार्थियों ने डिस्टिंक्शन सहित प्रथम श्रेणी तथा 177 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने बताया कि इस वर्ष 125 पदक प्रदान किए गए, जिनमें 74 पदक छात्राओं और 51 पदक छात्रों को मिले। कुल पदक विजेताओं में छात्राओं की हिस्सेदारी 59.20 प्रतिशत रही, जो उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्शाती है।

शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम : योगेंद्र उपाध्याय

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत का अर्थ सिद्धांत का अंत नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देना है। उन्होंने विद्यार्थियों से सकारात्मक सोच अपनाने और अपनी शिक्षा का उपयोग मानवता, समाज तथा देश के उत्थान के लिए करने का आह्वान किया।

मातृभाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण पर राज्यपाल का जोर

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय की छात्राएं लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने विश्वविद्यालय में चीनी, जापानी और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं के साथ अवधी भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रयास की सराहना करते हुए इसे स्थानीय भाषा, लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि लोकभाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की धड़कन होती हैं। विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही आधुनिक भाषा प्रयोगशाला विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा किए गए 71 एमओयू का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल समझौते करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित भी किया जाना चाहिए। उन्होंने शोध, अकादमिक सहयोग और छात्र आदान-प्रदान को समाज, शासन और शिक्षा व्यवस्था के लिए लाभकारी बताया।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी मातृभाषा के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया और कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा भी होना चाहिए। महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने एक प्रेरक उदाहरण देते हुए उस सब्जी विक्रेता का उल्लेख किया, जिसने सड़क किनारे मिली एक नवजात बच्ची को अपनाकर उसका पालन-पोषण किया और आगे चलकर वह बच्ची आईएएस अधिकारी बनी। उन्होंने कहा कि समाज में नकारात्मक घटनाओं के साथ-साथ ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण भी मौजूद हैं, जो मानवता में विश्वास मजबूत करते हैं।

स्वर्ण पदक विजेताओं ने साझा किए संघर्ष के अनुभव

अरबी भाषा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर तीन स्वर्ण पदक हासिल करने वाले अफान मोहम्मद इरफान ने बताया कि वे पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों के छात्रों को लेकर समाज में बनी धारणाओं को बदलने की आवश्यकता है। उनका लक्ष्य पीएचडी कर देश का नाम रोशन करना है। स्वर्ण पदक विजेता सौम्या मिश्रा ने बताया कि उन्होंने घर से दूर रहकर हॉस्टल में पढ़ाई की और अनेक कठिनाइयों का सामना किया। माता-पिता के सहयोग, अनुशासन और निरंतर मेहनत के बल पर उन्हें यह सफलता प्राप्त हुई।

संपादकीय

आस्था की सुरक्षा के लिए नई चुनौती

भारत में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन के केंद्र भी हैं। विशेष रूप से अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद देशभर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में यदि किसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी या सुरक्षा में चूक जैसी घटना सामने आती है, तो उसका असर केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे धार्मिक तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी कारण जब किसी प्रमुख मंदिर में चोरी या वित्तीय अनियमितता की घटना सामने आती है, तो प्रशासन अन्य मंदिरों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर देता है। इसका उद्देश्य केवल अपराधियों तक पहुँचना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना भी होता है। मंदिरों में बढ़ती सुरक्षा की आवश्यकता देश के अनेक बड़े मंदिरों में प्रतिदिन लाखों रुपये का चढ़ावा आता है। त्योहारों, विशेष अवसरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यह राशि कई गुना बढ़ जाती है। नकद दान के साथ-साथ सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ भी श्रद्धालु अर्पित करते हैं। ऐसे में इन मंदिरों की सुरक्षा किसी बैंक या अन्य महत्वपूर्ण संस्थान से कम चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाती। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग के बावजूद यदि निगरानी व्यवस्था में कहीं भी लापरवाही हो, तो चोरी या गबन जैसी घटनाएँ संभव हो सकती हैं। इसलिए केवल सीसीटीवी कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग की समीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था का समय-समय पर ऑडिट भी आवश्यक है। प्रशासन की बढ़ी सतर्कता- किसी प्रमुख मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन सामान्यतः अन्य प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का भी आकलन करते हैं। इसमें कई बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है— सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और उनकी कार्यक्षमता। चढ़ावे की गिनती और सुरक्षित भंडारण की प्रक्रिया। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और उनकी जवाबदेही। प्रवेश एवं निकास द्वारों की निगरानी। दानपात्र खोलने की पारदर्शी व्यवस्था। रिकॉर्ड रखने और डिजिटल निगरानी की प्रणाली। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत बनाए रखना होता है। तकनीक बन सकती है सबसे बड़ी सुरक्षा- आज कई प्रमुख मंदिर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, फेस रिकग्निशन, डिजिटल एक्सेस कंट्रोल, बायोमेट्रिक प्रवेश, अलार्म सिस्टम और कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्थाएँ सुरक्षा को मजबूत बना रही हैं। इसके अलावा चढ़ावे की गणना में भी मशीनों और डिजिटल रिकॉर्डिंग का उपयोग बढ़ रहा है। इससे मानवीय त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना कम होती है तथा प्रत्येक प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। श्रद्धालु मंदिर में दान केवल धार्मिक भावना से नहीं, बल्कि विश्वास के आधार पर करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। नियमित ऑडिट, सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जमा और बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था से लोगों का भरोसा और मजबूत होता है। यदि किसी मंदिर में वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो, तो चोरी या गबन की आशंकाएँ भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं मंदिरों की सुरक्षा केवल प्रशासन या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। मंदिर ट्रस्ट, कर्मचारी, स्वयंसेवक और श्रद्धालु भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देना, सुरक्षा नियमों का पालन करना और निगरानी व्यवस्था में सहयोग करना सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी एक घटना के आधार पर सभी मंदिरों की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं होगा। देश के अधिकांश मंदिरों में सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्थाएँ प्रभावी ढंग से संचालित होती हैं। फिर भी किसी भी घटना से सीख लेकर सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक कदम है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बड़े मंदिरों के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट, कर्मचारियों का सत्यापन, डिजिटल लेखा-जोखा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और नियमित प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएँ भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना को कम कर सकती हैं। मंदिरों की सुरक्षा केवल संपत्ति की रक्षा का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यदि किसी प्रमुख मंदिर में चोरी की घटना सामने आती है, तो उससे सबक लेते हुए अन्य मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण एक स्वाभाविक तथा आवश्यक प्रशासनिक कदम है। पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक, जवाबदेही और जनसहभागिता के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट बना रहे और मंदिर सुरक्षित, व्यवस्थित तथा विश्वसनीय धार्मिक केंद्र बने रहें।

राजीव शुक्ला -(संपादक)

मेष -मेष राशि आज आपको बातचीत और निर्णय लेने के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र में पहले से अधूरे पड़े कार्य दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है, जबकि नए समझौते सोच-समझकर करना उचित रहेगा। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा और पुराने मतभेद दूर होने के संकेत मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में सहयोग बना रहेगा।

वृषभ-आर्थिक मामलों में आज संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है, इसलिए बजट पर विशेष ध्यान दें। व्यापार में पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार में संयम रखना चाहिए।

मिथुन -आज किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें। कार्यक्षेत्र में पुराने अवसर दोबारा मिल सकते हैं, जिनका उचित लाभ उठाया जा सकता है। व्यापार में धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

कर्क -लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन अनुकूल माना जा सकता है। दूर स्थान या विदेश से जुड़े कार्यों में कुछ देरी संभव है। कार्यक्षेत्र में किसी भी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद ही आगे बढ़ें।

सिंह -आज मित्रों और सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखने से कार्यों में सफलता मिलेगी। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापार में अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

कन्या-कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ अपने कार्य पूरे करें। व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में विश्वास और सहयोग का वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से गर्दन या कंधों में हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम दें।

तुला-आज भाग्य आपका साथ दे सकता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना अधिक लाभकारी रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में पुराने अनुभव आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। परिवार में धार्मिक और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है।

वृश्चिक-धन और निवेश से जुड़े मामलों में आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े कार्यों में देरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में गोपनीय बातों को साझा करने से बचें। व्यापार में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें।

धनु -साझेदारी से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में सामूहिक प्रयासों से सफलता मिलने की संभावना है। व्यापार में पुराने सहयोगियों का साथ लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

मकर-कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें। संवाद की कमी के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में पुराने कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।

कुंभ-रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को पुराने विषयों की दोबारा तैयारी करने से लाभ होगा। नौकरी में नई योजनाओं को फिलहाल स्थगित रखना उचित रहेगा।

मीन-पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना लाभदायक रहेगा। संपत्ति या वाहन से जुड़े कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका अनुभव आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। व्यापार में परिवार का सहयोग मिलेगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से आगरा में युवाओं के स्वावलंबन और स्वरोजगार की नई उड़ान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' (डल्ट।) राज्य के शिक्षित और कुशल युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार प्रदाता के रूप में विकसित करना है। इसके तहत प्रदेश सरकार युवाओं को अपने नए उद्यम, स्टार्ट-अप या सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए बेहद आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को जमीनी स्तर पर एक नई मजबूती मिल रही है। यह अभियान उत्तर प्रदेश को 'वन ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को गति देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे युवाओं का पलायन थमा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। इसी कड़ी में आगरा जनपद में इस योजना का क्रियान्वयन अत्यंत प्रभावी ढंग से हो रहा है, जहां जिला प्रशासन और स्थानीय बैंक शाखाओं के सक्रिय सहयोग से युवाओं के सपने तेजी से साकार हो रहे हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशिष्ट वित्तीय संरचना है, जो नए उद्यमियों के लिए शुरुआती जोखिम को काफी कम कर देती है। इसके अंतर्गत युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि युवाओं को अपनी पूंजी के लिए साहूकारों या बैंकों की जटिल और महंगी ब्याज दरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। योग्य लाभार्थियों को योजना की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को सीधे लाभान्वित करना है, जिससे आने वाले समय में राज्य के भीतर लाखों नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों का जाल बिछाया जा सके। योजना के तहत पात्रता के लिए आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। आगरा जनपद में इस दूरदर्शी योजना के जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन और इसके सकारात्मक प्रभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण गोकुलपुरा निवासी श्री कृष्णा यादव हैं। सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के कारण उनके लिए स्वयं का उद्योग स्थापित करना आसान नहीं था। वे हमेशा अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते थे, लेकिन पूंजी की कमी उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। इसी दौरान उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी मिली। उन्होंने योजना का अध्ययन किया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए केनरा बैंक, सिकंदरा-बोदला रोड शाखा, आगरा से 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त किया।

इस वित्तीय सहायता से कृष्णा यादव ने कार्डबोर्ड उद्योग की स्थापना की। शुरुआत में बाजार की प्रतिस्पर्धा और उत्पादन प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनकी लगातार मेहनत और गुणवत्ता ने उनके व्यवसाय को सफलता की राह पर आगे बढ़ाया। आज उनकी इकाई सुचारु रूप से संचालित हो रही है और उन्होंने अपने साथ दो अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। इसी तरह आगरा के ही खातीपाड़ा, लोहमंडी के निवासी श्री परवीन अली ने भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को नई उड़ान दी है। वे लंबे समय से स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखते थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत आवेदन करने पर उनकी पात्रता के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा, आगरा शाखा द्वारा 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और सरकार की ओर से 50 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। प्राप्त वित्तीय सहायता से परवीन अली ने कारपेट उद्योग से संबंधित अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। आधुनिक संसाधनों और बेहतर प्रबंधन के साथ उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया और आज उनकी इकाई सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने व्यवसाय के माध्यम से उन्होंने 4 अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे उन परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार आया है। आगरा जनपद में योजना की शानदार सफलता को देखते हुए प्रशासन द्वारा युवाओं के स्वरोजगार और स्टार्टअप के सपनों को तेजी से साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष जनपद में शत-प्रतिशत ऋण वितरण सुनिश्चित किया गया है। युवा उद्यमियों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा तय लक्ष्यों में और अधिक वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जिले के अधिक से अधिक युवाओं को इस कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। वित्तीय सहायता के साथ-साथ यह अभियान युवाओं की व्यावसायिक क्षमता को निखारने पर भी पूरा ध्यान केंद्रित करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए कौशल प्रशिक्षण की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करती है कि जो भी उद्यम शुरू हो, वह बाजार की व्यावहारिक समझ के साथ आगे बढ़े। डिजिटल साक्षरता और आधुनिक व्यापारिक तौर-तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने न केवल युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं, बल्कि प्रदेश को देश के एक प्रमुख स्टार्टअप और उद्यमशीलता केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस नींव रख दी है। बिना गारंटी का यह ब्याज मुक्त ऋण युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की राह दिखा रहा है। सरकारी सहायता, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन, बैंक अधिकारियों के सहयोग और युवाओं के दृढ़ संकल्प के बल पर आज प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलंबन की नई इबारत लिख रहा है।

यह अभियान उत्तर प्रदेश को 'वन ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को गति देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे युवाओं का पलायन थमा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। इसी कड़ी में आगरा जनपद में इस योजना का क्रियान्वयन अत्यंत प्रभावी ढंग से हो रहा है, जहां जिला प्रशासन और स्थानीय बैंक शाखाओं के सक्रिय सहयोग से युवाओं के सपने तेजी से साकार हो रहे हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशिष्ट वित्तीय संरचना है, जो नए उद्यमियों के लिए शुरुआती जोखिम को काफी कम कर देती है।

जनपद- आगरा

ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना : श्रमिक रमेश की बेटी की धूमधाम से हुई शादी

गरीब परिवारों में बेटी की शादी हमेशा एक बड़ी चिंता का विषय रही है। दहेज, बारात और अन्य खर्चों का बोझ अक्सर माता-पिता को कर्ज के जाल में फंसा देता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना ऐसे ही गरीब श्रमिक परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों श्रमिकों की बेटियों के हाथ पीले करवाकर उनके सम्मान की रक्षा की है। कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र के एक कारखाने में काम करने वाले रमेश प्रसाद की कहानी भी इसी बदलाव की गवाह है। रमेश प्रसाद पिछले 15 वर्षों से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत एक चमड़ा फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी मासिक मजदूरी 18,000 रुपये है। इस सीमित आय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बड़ी बेटी सीमा की शादी की उम्र होने पर रमेश की चिंता बढ़ गई थी। बेटी की शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, यह सोचकर उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। साहूकार से कर्ज लेता तो पूरी जिंदगी ब्याज भरते निकल जाती। इसी दौरान रमेश को फैक्ट्री के श्रमिक कल्याण अधिकारी से ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के बारे में पता चला। अधिकारी ने बताया कि यदि श्रमिक की मासिक मजदूरी 24,000 रुपये से अधिक न हो तो उसकी पुत्री की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देती है। यह सुनकर रमेश की आँखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आवश्यक दस्तावेज जुटाए और श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दिया।

योजना के तहत पात्रता की जांच के बाद रमेश का आवेदन स्वीकृत हो गया। बेटी की शादी की तारीख तय होते ही श्रम विभाग द्वारा 51,000 रुपये की धनराशि सीधे रमेश के बैंक खाते में भेज दी गई। यह राशि समय पर मिलने से रमेश का बड़ा बोझ हल्का हो गया। श्रमिक श्री रमेश ने बताया कि सरकार से मिली इस मदद से मैंने बेटी के लिए जरूरी सामान खरीदा, बारातियों के खाने-पीने का इंतजाम किया और बिना किसी कर्ज के शादी संपन्न कराई। रमेश की बेटी सीमा की शादी पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई। बारात आई, द्वारचार हुआ, कन्यादान हुआ और बेटी हंसी-खुशी विदा हुई। मोहल्ले के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि एक मामूली श्रमिक की बेटी की शादी इतने अच्छे से कैसे हो गई।

रमेश गर्व से कहते हैं, आज मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश है। यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वजह से संभव हुआ है। अगर यह योजना न होती तो शायद मैं बेटी की शादी इतनी इज्जत से नहीं कर पाता। रमेश की पत्नी सुनीता देवी भावुक होकर कहती हैं, हम गरीबों के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा डर दोनों होता है। सरकार ने हमारी बेटी का कन्यादान कर के हमारा डर खत्म कर दिया। अब हम दूसरी बेटी की शादी के लिए भी निश्चित हैं। सरकार ने हम जैसे श्रमिकों को सच में सहारा दिया है। ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना प्रदेश के लाखों पंजीकृत कारखाना श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। सरकार द्वारा श्रमिको के कल्याण के लिए संचालित ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के अन्तर्गत 24,000 रुपये से कम मासिक आय वाले श्रमिकों को पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपये की सहायता देती है। यह योजना साबित करती है कि सरकार श्रमिकों के सुख-दुख में साथ खड़ी है। रमेश की बेटी की हंसी और उनके परिवार का सम्मान ही ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना की सबसे बड़ी सफलता है।

योजना के तहत पात्रता की जांच के बाद रमेश का आवेदन स्वीकृत हो गया। बेटी की शादी की तारीख तय होते ही श्रम विभाग द्वारा 51,000 रुपये की धनराशि सीधे रमेश के बैंक खाते में भेज दी गई। यह राशि समय पर मिलने से रमेश का बड़ा बोझ हल्का हो गया। श्रमिक श्री रमेश ने बताया कि सरकार से मिली इस मदद से मैंने बेटी के लिए जरूरी सामान खरीदा, बारातियों के खाने-पीने का इंतजाम किया और बिना किसी कर्ज के शादी संपन्न कराई। रमेश की बेटी सीमा की शादी पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई। बारात आई, द्वारचार हुआ, कन्यादान हुआ और बेटी हंसी-खुशी विदा हुई। मोहल्ले के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि एक मामूली श्रमिक की बेटी की शादी इतने अच्छे से कैसे हो गई।

-सोनी सिंह, सूचना अधिकारी

घरेलू श्रम को सम्मान से मातृशक्ति को मिलेगी प्रतिष्ठा

भारतीय समाज में गृहिणियों को हमेशा से परिवार की धुरी माना जाता रहा है, किंतु घरेलू कार्यों में उनके अथक योगदान के बावजूद वे कभी आर्थिक विमर्श का केंद्र नहीं रहीं। इसी संदर्भ में हाल ही में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली गृहिणियों के मुआवजे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके श्रम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। महिलाओं के घरेलू कार्यों की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 17 प्रतिशत हिस्सेदारी मानी जाती है। ऐसे में निश्चित रूप से किसी गृहिणी के वास्तविक

योगदान का मूल्य आंका जाना बेहद जरूरी है, दरअसल ,यह फैसला घरेलू श्रम को सम्मान और पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही यह उस रूढ़िवादी सोच पर भी प्रहार है, जो महिलाओं के अवैतनिक श्रम को अनुत्पादक मानती रही है।दरअसल भारतीय समाज में एक अजीब भ्रम लंबे समय से रहा है कि घर अपने आप चलता है। रसोई में खाना खुद बनता है, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं और कपड़े खुद धुल जाते हैं। लेकिन असल में इस चमत्कार का नाम है गृहिणी। उसे हर काम करते हुए देखा जाता है, किंतु कमाते हुए नहीं माना जाता। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस भ्रम को तोड़ा था। जब अदालत ने कहा कि नौकरी न करने वाली पत्नी को 'बेकार' नहीं कहा जा सकता। यह केवल कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि सामाजिक आईना है। इसमें वह चेहरा साफ दिखता है, जिसे समाज देखने से बचता रहा है। एक गृहिणी का श्रम भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अदृश्य स्तंभ है।हाल के अध्ययनों से भी स्पष्ट होता है कि घरेलू श्रम का आर्थिक महत्व बेहद बड़ा है।

भारत के 2024 के समय-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएं प्रतिदिन औसतन 305 मिनट (करीब 5 घंटे) अवैतनिक घरेलू सेवाओं में लगाती हैं, जबकि पुरुष औसतन 98 मिनट ही देते हैं। वे परिवार के सदस्यों की देखभाल जैसे अवैतनिक देखभाल कार्यों में भी पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं। दूसरी ओर, 2024 की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी में सुधार के बावजूद वेतनयुक्त कार्यों के साथ-साथ घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ बना हुआ है। साल 2024 के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भी पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गृहिणियां भोजन बनाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, सफाई, पानी और अन्य घरेलू प्रबंधन जैसे कार्यों में प्रतिदिन कई घंटे लगाती हैं, जिनका बाजार मूल्यांकन किया जाए तो परिवारों को इसके लिए बड़ी राशि खर्च करनी पड़े। अनेक अर्थशास्त्री मानते हैं कि यदि अवैतनिक घरेलू श्रम को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाए।

पारिवारिक त्याग की अनदेखी कर आज़ादी की चाह

फरीदाबाद में राहुल नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने वीडियो बनाया और कहा कि वह घर के सारे काम करता है, व्यापार भी करता है, फिर भी उसकी पत्नी उसे मारती-पीटती है। दूसरा किस्सा पुणे के केतन का है, कहा गया कि उसकी मंगेतर सिया ने अपने मित्र चेतन की मदद से उसे लोहागढ़ पहाड़ी से धक्का दे दिया। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वह हकलाता भी था। इन दोनों मामलों में युवाओं ने जान गंवाई। इनके घर वालों, परिजनों पर क्या गुजरी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मगर अफसोस की बात ये है कि इन दोनों की मृत्यु को स्त्री अधिकारों के नाम पर सेलिब्रेट किया गया। कहा गया कि अब तक स्त्रियां सहती रही हैं, मगर अब वे बदला ले रही हैं। मुस्कान सोनी नाम की दांतों की डॉक्टर ने तो बाकायदा केतन की मौत का मजाक उड़ाया कि उसके साथ तो ऐसा होना ही था और हा-हा-हा करते वीडियो पोस्ट किया। हालांकि बाद में इस डॉक्टर ने माफी भी मांगी।जब हम

अधिकारों की बात करते हैं, तो उनका अर्थ हमारे दैनंदिन जीवन की सुविधाओं से जुड़ा होता है। छोटे, बड़े की भावना को खत्म करने की बात होती है। लेकिन मृत्यु पर हंसना, मीम्स बनाना, कहना कि वक्त आ गया है कि अब स्त्रियों को अपने प्रति किए गए हर अपराध का बदला लेना चाहिए, कितना दुखद है। अंग्रेजी की एक बड़ी लेखिका और एक बड़े लेखक ने तो यह तक कहा कि सिया ने केतन को मारा, इसके लिए सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि हमारे परिवारों का ढांचा जिम्मेदार है। जहां लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं। वे न अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, न देर रात लौट सकती हैं, न शराब पी सकती हैं। ऐसा कहने वाले वे लोग हैं, जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले हैं। जिनके इर्द-गिर्द सेवकों और सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज है, लेकिन ज्ञान वे उन आम लड़कियों को दे रहे हैं, जो अमूमन अपराध की जद में होती हैं। 'अपनी सुरक्षा अपने हाथ' वाली कहावत इन पर चरितार्थ होती है। फिर देर रात तक पार्टी करना या शराब पीना आम लड़कियों का जीवन नहीं है। और क्या स्त्रियों के लिए शराब पीना इतनी अच्छी बात है। फिर ऐसा क्यों है कि अक्सर महिलाएं अपने घर के आसपास शराब के ठेके खुलने का विरोध करती हैं। शराबबंदी की मांग करती हैं क्योंकि शराब के कारण ही उनके पति तरह-तरह की हिंसा करते हैं। यदि वे पैसे भी कमाएं, तो उनके पैसे शराब पीने के लिए छीन लिए जाते हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गांधी जी जिन्होंने कहा था कि शराब आत्मा का नाश करती है, उनकी इस शिक्षा को भी लोग भूल गए हैं। डाक्टरों की सलाह भी याद नहीं रखते, जो कहते हैं कि शराब पीने से शरीर के तमाम अंगों पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। यदि इन लोगों की मानें तो देश में चलने वाले जितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। लेकिन 'माई लाइफ और माई च्वाइस' का विचार एलीट स्त्री-पुरुषों के मन में इतना बसा हुआ है कि वे अपनी शर्तों को दूसरों पर लाद रहे हैं और इन्हें ही दूसरों की च्वाइस बता रहे हैं। वे सिया का बचाव करते हुए उसके घर वालों और हर एक के घर वालों को दोष दे रहे हैं। पश्चिम का उदाहरण बार-बार दिया जा रहा है कि वहां देखो स्त्रियों को कितनी आजादी है। क्या सचमुच! अपने यहां माता-पिता बच्चों को हमेशा बच्चा मानते हुए, उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई का खर्चा उठाते हैं। पढ़ने के लिए विदेश भेजते है। करोड़ों रुपये का लोन लेते हैं, उसे खुद चुकाते हैं। बच्चों के लिए घर बनाते हैं। यानि कि अपनी उम्र और सारे संसाधन वे बच्चों के लिए लगा देते हैं, जिससे उनका जीवन आसान हो सके। माता-पिता के सारे संसाधन चाहिए, लेकिन जीवन अपनी शर्तों पर जीना है। कौन रोकता है, लेकिन फिर संसाधन भी खुद जुटाइए। माता-पिता की जमीन-जायदाद में भी हिस्सा मत मांगिए। बीमारी-हारी में भी अपनी मदद खुद कीजिए। ड्रीम वैडिंग करना हो, तो खुद पैसे जुटाइए। उनके सम्पर्कों का भी लाभ मत उठाइए।अधिकार बिना कर्तव्यों के नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हां मन की बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं चुकाते। विदेशों में कई ऐसे आदमियों से मिली, जिनकी उम्र पचास के पार है, लेकिन अभी तक वे अपनी पढ़ाई के लिए उठाए गए कर्ज को चुका रहे हैं। भारत में तो माता-पिता की हालत ये है कि ताउम्र खटते भी हैं और पिटते भी हैं। बातें बनाते रहिए कि बुजुर्गों के लिए क्या-क्या होना चाहिए। विमर्शों की नकारात्मकता कितनी है कि जहां मौत का भी जश्न मनाया जाए।

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

यूपी को देश का अग्रणी कौशलयुक्त राज्य बनाने में जुटी योगी सरकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीक, उद्योगों की आवश्यकताओं तथा रोजगारोन्मुखी कौशल से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने सोमवार को विधानभवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक युवा को हुनरमंद बनाकर रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभाग की सभी योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए तथा प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र की प्रगति की सतत निगरानी

रखी जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के साथ करें। कौशल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए युवाओं के लिए अधिक से अधिक शॉर्ट टर्म एवं रोजगारपरक कौशल पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सॉफ्ट स्किल, डिजिटल लर्निंग, संवाद कौशल, इंटरव्यू तैयारी, रिज्यूमे लेखन तथा व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की रोजगार क्षमता और अधिक बढ़ सके। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार की मंशा केवल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है। इसलिए विभाग उद्योगों के साथ मजबूत समन्वय स्थापित करे तथा स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आईटीआई एवं कौशल विकास संस्थानों में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों की जानकारी अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाई जाए ताकि प्रत्येक इच्छुक अभ्यर्थी को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिल सके। बैठक में अटल आवासीय विद्यालयों में संचालित स्किलिंग कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जिसमें बताया गया कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही अगले माह से आश्रम पद्धति विद्यालयों में भी स्किलिंग कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को भी तकनीकी दक्षता प्राप्त हो सके। मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। ऐसे युवाओं के वीडियो, अनुभव एवं उपलब्धियों को सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से साझा किया जाए ताकि अधिक से अधिक युवा प्रेरित होकर कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़ें। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सीएनसी, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग तथा इंडस्ट्री 4.0 से संबंधित प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने उद्योगों के साथ साझेदारी मजबूत करने, प्रशिक्षण सामग्री को समय-समय पर अद्यतन करने तथा विद्यार्थियों को वास्तविक औद्योगिक वातावरण के अनुरूप तैयार करने पर विशेष बल दिया।

सीतापुर में 12 जुलाई को रोपे जाएंगे 82 लाख पौधे

विकसित होंगे ऊर्जा और कपि वन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। 12 जुलाई को जिले के विभिन्न हिस्सों में 82 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। पौधरोपण की निगरानी चुनावी मोड में होगी। वन के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भ्रमण करके पौधारोपण का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वन विभाग की साइट पर हर घंटे पौधरोपण का विवरण और फोटो अपलोड होती रहेंगी। इस बार ऊर्जा और कपि दो विशेष वन भी विकसित किए जाएंगे। वन विभाग के साथ ही विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, रेलवे, परिवहन, उद्यान, पंचायत राज आदि विभागों ने अपने कर्मचारियों को पौधों को लगाने और संरक्षित करने का प्रशिक्षण दिलवा दिया है। बड़े स्थलों की बैरीकेडिंग करने के बाद ही पौधारोपण कराने को कहा गया है। इस बार वन विभाग के साथ ही अन्य विभागों ने भी रोपे गए पौधों में से कम से कम 75 प्रतिशत को वृक्ष बनाने का संकल्प लिया है। सर्वाधिक 32 लाख 54 हजार पौधे ग्राम्य विकास विभाग की ओर से रोपे जाएंगे।

विभाग प्रधानों के माध्यम से ग्रामीणों को आम, इमली, नींबू, कटहल, अमरूद, अशोक, नीम, बकैना आदि के पौधे दिए जाएंगे। दरवाजों पर रोपे जाने के लिए इस बार वन विभाग की ओर सात लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को सहजन के भी पौधे दिए जाएंगे।

वन क्षेत्राधिकारी देंगे रिपोर्ट

इस बार सिर्फ पौधारोपण की नहीं उनकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने सभी वन क्षेत्राधिकारियों को पौधारोपण के बाद सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देने की व्यवस्था भी बना दी है। वन क्षेत्राधिकारियों को अपने विभाग के साथ ही अन्य विभागों की ओर से रोपे गए पौधों की भी मानीटरिंग करनी होगी। ग्रामीणों को जागरूक करके पौधों की रक्षा के लिए प्रेरित करेंगे।

नैमिषारण्य के आसपास होगा वृहद पौधारोपण

वन विभाग ने नैमिषारण्य के साथ ही आसपास के गांवों में वृहद पौधारोपण की योजना बनाई है। ग्रामीणों से संपर्क करके औषधीय पौधों को लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके अलावा तीर्थनगरी में रिक्त पड़े भूखंडों पर पौधारोपण किया जाएगा।इस अवसर पर नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार जी, स्थानीय पार्षद श्री मुकेश सिंह 'मोंटी' जी, अपर नगर आयुक्त श्री अरुण कुमार गुप्त जी, उप नगर आयुक्त श्रीमती रश्मि भारती जी, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी श्री महामिलिंद लाल जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री साहब लाल मिश्रा जी सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अवशेष पात्रों को अभियान चलाकर जारी हों नए राशन कार्ड : मनोज पाण्डेय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शेष पात्र लाभार्थियों की पहचान कर अभियान चलाकर नए राशन कार्ड जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉस मशीनों में नेटवर्क संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए। विधान भवन सभागार में आयोजित रसद स्थायी समिति (2025-26) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने विभागीय योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त अतुल सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत 15.20 करोड़ यूनिट का आच्छादन निर्धारित है, जबकि वर्तमान में 14.64 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर मंत्री ने शेष पात्र व्यक्तियों को भी योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डों की जांच शासनादेशों के अनुरूप निष्पक्ष ढंग से की जाए। समिति के सदस्यों ने कई जिलों में ई-पॉस मशीनों में नेटवर्क की समस्या के कारण राशन वितरण में देरी और लाभार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री ने जिलाधिकारियों और बीएसएनएल अधिकारियों के समन्वय से नेटवर्क संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि इन भवनों का निर्माण परिवहनीय मार्गों के किनारे तथा आबादी के निकट कराया जाए, ताकि लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में सुविधा हो। बैठक में यह सुझाव भी दिया गया कि अन्नपूर्णा भवनों में आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की जाए।

बिना लेआउट पास कराए हो रही प्लॉटिंग पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

सीतापुर के मिरदही टोला में बिना लेआउट पास कराए की जा रही 13 बीघा अवैध प्लाटिंग को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। मिरदही टोला में बिना लेआउट पास कराए की जा रही प्लाटिंग को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया। यहां पर करीब 13 बीघा भूमि पर बिना लेआउट को स्वीकृत कराए अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। भूमि की कीमत 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है। विनियमित क्षेत्र में की जा रही इस अवैध प्लाटिंग की जानकारी तहसील प्रशासन को लगी तो जांच करना शुरू किया। इसमें बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग कराए जाने की पुष्टि हुई। इस पर नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडेय के निर्देश पर विनियमित क्षेत्र की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध निर्माण और प्लाटिंग के लिए किए गए विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया।

पुराने सीतापुर में कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए इसके लिए पर्याप्त पुलिसबल को तैनात कराया गया था। पुलिस के जवानों ने पहले चारों ओर से क्षेत्र को घेर लिया। इसके बाद बुलडोजर से प्लाट के लिए लगाई गई ईंटों, आरसीसी रोड को तोड़ दिया गया।

अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप

विनियमित क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से अन्य जमीन कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। शहर के सीमावर्ती क्षेत्र में कांशीराम कालोनी के पास लेकर खैराबाद तक अनेक स्थानों पर प्लाटिंग की जा रही है। इनमें से अधिकांश के मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं। इसके अलावा सीवर सिस्टम, प्रकाश तक की व्यवस्था नहीं है। सोमवार को हुई कार्रवाई से कारोबारियों में भी भय व्याप्त हो गया है।

"संबंधित जमीन का मालिकाना हक किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। प्लाट काटकर बेचने का कार्य पप्पू जायसवाल और विकास चतुर्वेदी कर रहे थे। इसकी शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। -एमके मिश्र, अवर अभियंता, विनियमित क्षेत्र"

वी-बी जी राम जी योजना को गति देने के लिए मोहनलालगंज ब्लॉक में मंथन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज (लखनऊ)। केन्द्र सरकार की नई वी-बी जी राम जी योजना एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृक्षारोपण महाभियान को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मंगलवार को विकास खण्ड मोहनलालगंज के अटल बिहारी बाजपेई सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खण्ड विकास अधिकारी शिवकुमार ने की, जबकि संचालन एवं तकनीकी मार्गदर्शन एपीओ उदय राज शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में विकास खण्ड के सभी तकनीकी सहायकों एवं ग्राम रोजगार सेवकों ने भाग लिया। अधिकारियों ने योजना के सफल क्रियान्वयन, कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध प्रगति तथा जियो टैगिंग एवं ऑनलाइन फीडिंग सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार चल रहे व्यापक वृक्षारोपण महाभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण कराया जाए तथा उसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में मौजूद ग्राम रोजगार सेवकों एवं तकनीकी सहायकों को निर्देशित किया गया कि वे आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का शत-प्रतिशत पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिल सके।

संक्षिप्त खबरें

यूपीईएसएससी ने प्रवक्ता भर्ती-2022 का अंतिम परिणाम घोषित, 18 विषयों के 624 पदों पर चयन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (बालक/बालिका) भर्ती-2022 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि विज्ञापन संख्या-02/2022 के अंतर्गत 18 विषयों के कुल 624 प्रवक्ता पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवा में अवसर उपलब्ध कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में प्रवक्ता भर्ती-2022 की पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता और शुचिता के साथ संपन्न कराई गई। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

12 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग लगाएगा 20 लाख पौध

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 12 जुलाई को आयोजित होने वाले 'वृक्षारोपण महायज्ञ-2026' में उच्च शिक्षा विभाग 20 लाख पौधरोपण करेगा। इस अभियान में प्रदेश के 77 विश्वविद्यालयों और करीब 8 हजार महाविद्यालयों की भागीदारी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश के लगभग 50 लाख छात्रों की सहभागिता से हरित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य और मजबूत होगा। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने वृक्षारोपण को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जोड़कर जन-आंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण महायज्ञ का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन स्थापित करना और प्रदेश में हरित आवरण का विस्तार करना है। योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में 22 सरकारी विश्वविद्यालय, 56 निजी विश्वविद्यालय तथा लगभग 8 हजार महाविद्यालय हैं, जिनमें करीब 50 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। यदि प्रत्येक छात्र एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो यह अभियान ऐतिहासिक सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि अधिकांश शिक्षण संस्थानों में परिसर सुरक्षित हैं, जिससे पौधों का संरक्षण भी बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों, कुलपतियों, कुलसचिवों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जाए। जिन संस्थानों में चारदीवारी नहीं है, वहां परिसर की सीमा पर पौधरोपण कर प्राकृतिक हरित बाउंड्री विकसित की जाए, जबकि जिन परिसरों में बाउंड्री मौजूद है वहां उसके किनारे सघन पौधरोपण कराया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने वृक्षारोपण को 'एक पेड़ माँ के नाम', 'गुरु के नाम' तथा रक्षाबंधन पर 'भाई-बहन के नाम' जैसे भावनात्मक अभियानों से जोड़ा है, ताकि लोग पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल भी करें।

रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों ने यूपीएसआईएफएस का परिभ्रमण किया

साइबर युग में अपराध के तरीके बदल रहे हैं, रहना होगा सावधान: डॉ0 जी.के. गोस्वामी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 7 जुलाई 2026 उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में आज रक्षा लेखा विभाग, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (RTC कैंट लखनऊ) में प्रशिक्षणरत रक्षा लेखा विभाग के 40 अधिकारियों ने परिभ्रमण किया। जिन्हें संस्थान के विषय विशेषज्ञों द्वारा साइबर एवं फोरेंसिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर संस्थापक निदेशक डॉ0 जी.के. गोस्वामी ने सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारियो को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर युग में अपराध के तरीके बदल रहे हैं इसलिए हमें सावधान रहना होगा पहले फिजीकल दुनियां में अपराध होते थे लेकिन अब डिजीटल दुनियां में अपराध हो रहे है ऐसे में तकनीक के बारे मे हम सभी को अधिक से अधिक जानकारी रखनी होगी और उसी के अनुसार कार्य करना होगा अन्यथा साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने डेटा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिसके पास जितना डेटा होगा वह उतना ही मजबूत होगा, कुछ देश इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि वह अपनी तकनीक और डाटा अन्य देशो से शेयर नहीं करते उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों का प्रशिक्षण का काल है जितना जिज्ञासु होगें उतना ही नई-नई चीजों को सीख पायेगें।यह संस्थान वर्तमान में साइबर सुरक्षा तथा फोरेंसिक विषय में विभिन्न संस्थानों को तकनीकी दक्षता आज निपुण कर रहा है। इस अवसर पर, उप निदेशक चिरंजीब मुखर्जी, मीना ने प्रशिक्षु अधिकारियो को संस्थान के बारे में ब्रीफ किया तथा आज के युग में साइबर फोरेंसिक क्यों महत्वपूर्ण है? इस विषय पर प्रकाश डाला कार्यक्रम के अंत में उप निदेशक जितेन्द्र श्रीवास्तव ने सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारियों का अभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी संतोष तिवारी ने तथा डॉ इंद्रजीत ने साइबर विषय पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षु अधिकारियो ने डीएनए तथा एआई लैब का भी विजिट किया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक हेमराज अतुल यादव, डॉ0 आनंद प्रकाश, अमित मिश्र, राहुल दिवेदी, डॉ0 पलक, आरआई शैलेन्द्र सिंह एवं कार्तिकेय सहित अन्य उपस्थित रहे।

जिन्हें संस्थान के विषय विशेषज्ञों द्वारा साइबर एवं फोरेंसिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर संस्थापक निदेशक डॉ0 जी.के. गोस्वामी ने सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारियो को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर युग में अपराध के तरीके बदल रहे हैं इसलिए हमें सावधान रहना होगा पहले फिजीकल दुनियां में अपराध होते थे लेकिन अब डिजीटल दुनियां में अपराध हो रहे है ऐसे में तकनीक के बारे मे हम सभी को अधिक से अधिक जानकारी रखनी होगी और उसी के अनुसार कार्य करना होगा अन्यथा साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं।

बारिश से पहले पंपिंग स्टेशन, सीवर और नालों की सफाई पूरी करें, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: ए.के. शर्मा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वर्षाकाल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि बारिश शुरू होने से पहले पंपिंग स्टेशनों, सीवर नेटवर्क और नालों की सफाई का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जलभराव, सीवर ओवरफ्लो अथवा सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सोमवार को लखनऊ स्थित संगम सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों की वर्षा पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान आमजन को जलभराव, गंदगी, कचरे के ढेर और सीवर बैक फ्लो

जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी निकाय युद्धस्तर पर विशेष अभियान चलाएं। मंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में संक्रामक रोग फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसे देखते हुए सभी निकाय नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर, एंटी-लार्वा दवाओं तथा अन्य आवश्यक रसायनों का छिड़काव सुनिश्चित करें, ताकि संक्रमण और महामारी की संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी पंपिंग स्टेशन और पंपिंग सेट स्थापित हैं, उनका तत्काल रखरखाव पूरा किया जाए तथा उन्हें पहले से चलाकर परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान मशीनों के खराब होने या रखरखाव का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी मशीनें हर समय पूर्ण रूप से कार्यशील स्थिति में रहनी चाहिए। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद और आगरा नगर निगमों के अलावा मुजफ्फरनगर, मऊ, पीलीभीत सहित विभिन्न नगर पालिकाओं एवं निकायों के अधिकारियों से वर्षा पूर्व तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने नगर आयुक्तों को निर्देशित किया कि सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग स्वयं करें तथा नागरिकों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी सीवर ओवरफ्लो, नालियों की सफाई में लापरवाही, जलभराव या स्वच्छता व्यवस्था में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव गुरुप्रसाद, निदेशक अनुज कुमार झा, विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल, मिशन निदेशक ऋतु सुहास सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश के सभी नगर आयुक्त एवं संबंधित अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद और आगरा नगर निगमों के अलावा मुजफ्फरनगर, मऊ, पीलीभीत सहित विभिन्न नगर पालिकाओं एवं निकायों के अधिकारियों से वर्षा पूर्व तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने नगर आयुक्तों को निर्देशित किया कि सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग स्वयं करें तथा नागरिकों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

चार नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा पर जोर, आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले मंत्री आशीष पटेल ने मंगलवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती और गोंडा के चार नवनिर्मित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रशासकीय परिषद की बैठक की। बैठक में कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने, निर्माण कार्य और आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सरदार वल्लभभाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती, मां पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोंडा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रतापगढ़ तथा सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मिर्जापुर की स्थापना की जा रही है। इन संस्थानों के शुरू होने से पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आशीष पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉलेजों में भवन, प्रयोगशालाएं, वर्कशॉप, पुस्तकालय और छात्रावास सहित सभी मूलभूत सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा का बेहतर वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि बदलते औद्योगिक परिवेश को देखते हुए नए इंजीनियरिंग कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंडस्ट्री 4.0 जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही स्थानीय उद्योगों के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

Notice

This is to inform the general public that my name is Anshu Singh, daughter of Narendra Singh, resident of Baraipar, Nwaijepar, District Gorak hpur, Uttar Pradesh. I wish to state that in TATA AIG Life Insurance policy number C102196236, my name is recorded as "Kumari Anshu," whereas my correct name, as per my Aadhaar card and other identity documents, is "Anshu Singh." Both these names refer to the same person, and that person is me. Therefore, I should be known and recognized by both these names.

सीरिया दौरे पर थे मैक्रों, तभी दमिश्क में धमाकों से दहला इलाका

पेरिस(एजेंसी)। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की ऐतिहासिक सीरिया यात्रा के दौरान मंगलवार को राजधानी दमिश्क में कई विस्फोट हुए। सीरिया के सरकारी मीडिया के अनुसार, इन धमाकों में कम से कम चार लोग घायल हो गए। मैक्रों जब सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे तभी 'फोर सीजन्स होटल' के निकट विस्फोट हुए। हालांकि, सीरियाई अधिकारियों ने घटना पर तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। सीरिया की मीडिया के अनुसार, मैक्रों इसी 'फोर सीजन्स' होटल में ठहरे हुए हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ बैठक जारी है। मैक्रों, अहमद अल-शरा के सत्ता में आने के बाद सीरिया का दौरा करने वाले पश्चिमी देशों के प्रमुख नेता हैं। उनकी यह यात्रा तुर्किये की राजधानी अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है।मैक्रों ने सीरिया पर लगे अधिकांश प्रतिबंध हटाने के लिए यूरोप और अमेरिका को राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह सोमवार रात एक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ सीरिया पहुंचे। इस दौरान उनके और राष्ट्रपति अल-शरा के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने हैं। युद्ध से तबाह सीरिया निवेशकों को आकर्षित कर देश के पुनर्निर्माण को गति देना चाहता है। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि राजधानी के मध्य क्षेत्र में दोनों विस्फोट, संवर्धित विस्फोटक उपकरणों के जरिए किए गए।इनमें से एक उपकरण कूड़ेदान में रखा गया था, जबकि दूसरा एक खड़ी कार में रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोटों में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल किसी की मौत की सूचना नहीं है। घटना की जांच जारी है। विस्फोट स्थल से धुएं का घना गुबार उठता देखा गया। यह इलाका दमिश्क की एक व्यस्त सड़क पर स्थित है और पर्यटन मंत्रालय के मुख्यालय तथा दमिश्क राष्ट्रीय संग्रहालय के निकट है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक वैन और एक मोटरसाइकिल आग की लपटों में घिरी दिखाई दे रही हैं, जबकि सड़क पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह घटना उस हमले के कुछ ही दिन बाद हुई है, जिसमें दमिश्क के जस्टिस पैलेस के पास एक कैफे में विस्फोटक उपकरण से हमला किया गया था। उस हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये विस्फोट राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं। अल-शरा ने वर्ष 2024 में विद्रोह का नेतृत्व करते हुए बशर अल-असद की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था।

जगन्नाथ मंदिर समिति ने राष्ट्रपति-पीएम को लिखा पत्र

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी नीति बनाने वाली संस्था है। दिब्यसिंह देब ने चार जुलाई को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, पिछले करीब दो दशकों से श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (पुरी) इस जरूरी मुद्दे को सुलझाने के लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, ओडिशा सरकार भी समय-समय पर इस बारे में बयान देती रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत के बाहर इस्कॉन की ओर से की जा रही समय से पहले श्री जगन्नाथ यात्राओं को रोकने में सफलता नहीं मिली।

भुवनेश्वर (ओडिशा)(एजेंसी)। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) के अध्यक्ष और गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि इस्कॉन की ओर से दुनियाभर में भगवान जगन्नाथ की समय से पहले निकाली जा रही 'स्नान यात्रा' और 'रथ यात्रा' को रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि इस्कॉन सदियों पुरानी परंपरा से अलग हटकर ये आयोजन कर रहा है, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। पुरी के गजपति महाराजा दिव्यसिंह ने कहा, कई बार अनुरोध करने के बाद भी इस्कॉन भगवान जगन्नाथ के त्योहारों के आयोजन में पवित्र शास्त्रों और सदियों पुरानी परंपराओं के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति (एसजेटीएमसी) ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी नीति बनाने वाली संस्था है। दिब्यसिंह देब ने चार जुलाई को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, पिछले करीब दो दशकों से श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (पुरी) इस जरूरी मुद्दे को सुलझाने के लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, ओडिशा सरकार भी समय-समय पर इस बारे में बयान देती रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत के बाहर इस्कॉन की ओर से की जा रही समय से पहले श्री जगन्नाथ यात्राओं को रोकने में सफलता नहीं मिली। भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक माने जाने वाले दिब्यसिंह देब ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की गौरवशाली परंपरा की पवित्रता को दुनियाभर में बनाए रखने और भारत व विदेश में रहने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से दोबारा अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वह ऐसे कदम उठाएं, जिससे इस्कॉन की ओर से शास्त्रों और परंपराओं के खिलाफ आयोजित की जा रही समय से पहले 'स्नान यात्रा' और 'रथ यात्रा' को रोका जा सके। श्री जगन्नाथ संस्कृति पर शोध करने वाले प्रोफेसर हरेकृष्ण सत्पथी ने कहा, इससे पहले दिब्यसिंह देब ने प्रधानमंत्री मोदी को 24 अक्तूबर 2025 और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 20 अप्रैल 2026 को पत्र लिखा था। इसलिए एसजेटीएमसी ने दिल्ली एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात करेगा और उन्हें श्री जगन्नाथ संस्कृति की पवित्रता बनाए रखने के महत्व के बारे में बताएगा। दिब्यसिंह देब ने माना कि केवल ओडिशा सरकार और जगन्नाथ मंदिर प्रशासन भारत के बाहर इस्कॉन की ओर से समय से पहले होने वाली रथ यात्रा को नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा, हमने इस मामले को ओडिशा के मुख्यमंत्री, कानून मंत्री, सांसदों और विधायकों के सामने उठाया है, ताकि सभी मिलकर इस मुद्दे पर काम करें और पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा को बचाया जा सके।

डिजिटल दौर में आंखों का रखें ख्याल आयुर्वेद के ये आसान उपाय आएंगे काम

आज के समय में मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लगातार स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में थकान, जलन, सूखापन और रोशनी से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में आंखों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी हो गया है। आयुर्वेद में आंखों को शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग माना गया है और इन्हें स्वस्थ रखने के लिए कई आसान उपाय बताए गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार, आंखों की समस्याओं के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण हो सकते हैं। पहला, आंखों का जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करना। दूसरा, अपनी जीवनशैली और आदतों में लापरवाही करना। तीसरा, मौसम में होने वाले असामान्य बदलाव। इनसे बचने के लिए सही खानपान, अच्छी दिनचर्या और कुछ प्राकृतिक उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है। आंखों की देखभाल के लिए पादाभ्यंग (पैरों की तेल से मालिश) को भी लाभकारी बताया गया है। रोजाना गुनगुने तेल से पैरों की मालिश करने से शरीर को आराम मिलता है और आंखों की थकान कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ठंडे पानी से आंखों को धोना भी एक आसान उपाय है। दिन में कुछ बार आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने से ताजगी महसूस होती है। आयुर्वेद और योग में आंखों के लिए कई तरह के अभ्यास बताए गए हैं। इनमें पामिंग एक सरल तरीका है। इसमें आंखें बंद करके हथेलियों से उन्हें ढककर कुछ देर आराम किया जाता है। इससे आंखों को आराम मिलता है और तनाव कम महसूस होता है। इसी तरह आंखों को धीरे-धीरे दाएं-बाएं घुमाने जैसे अभ्यास भी आंखों की मांसपेशियों को सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं। सूर्य की हल्की रोशनी में बैठना, मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करना और त्राटक जैसे योग अभ्यास भी पारंपरिक रूप से आंखों के लिए उपयोगी माने जाते हैं। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बुरी आदतों से बचना भी जरूरी है। ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से बचें, पर्याप्त नींद लें और आंखों पर अनावश्यक दबाव न डालें। इसके अलावा, पढ़ते समय पर्याप्त रोशनी का ध्यान रखें और किताब या स्क्रीन को आंखों से उचित दूरी पर रखें। समय-समय पर आंखों को आराम देना भी जरूरी है। लंबे समय तक आंखों में परेशानी, धुंधला दिखाई देना या दर्द जैसी समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में रखा कदम, फिर बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में एक बनीं

उनके पिता का नाम दर्शन सिंह और मां का नाम राजी कौर था। हालांकि, बेहद कम उम्र में पिता के निधन के बाद नीतू परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने लगी। नीतू सिंह का असली नाम हरनीत कौर था लेकिन फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के दौरान उन्हें 'बेबी सोनिया' या 'बेबी नीतू' के स्क्रीन नाम से जाना जाने लगा।

बॉलीवुड ने हर दशक में एक से बढ़कर एक दिग्गज अभिनेत्री पाई है, जिन्होंने अपनी शानदार अभिनय, बेमिसाल खूबसूरती और लाजवाब डांस मूव्स से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाने और लाखों दर्शकों के दिलों पर राज करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं हिंदी चलचित्र अभिनेत्रियों में एक नीतू सिंह हैं, जो अब नीतू कपूर के नाम से जानी जाती हैं। बॉलीवुड की 1960 और 1970 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में एक, नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को नई दिल्ली में एक पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दर्शन सिंह और मां का नाम राजी कौर था। हालांकि, बेहद कम उम्र में पिता के निधन के बाद नीतू परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने लगी। नीतू सिंह का असली नाम हरनीत कौर था लेकिन फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के दौरान उन्हें 'बेबी सोनिया' या 'बेबी नीतू' के स्क्रीन नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद में फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी शुरुआत के साथ उन्हें 'नीतू सिंह' नाम दिया गया। बाल कलाकार के रूप में नीतू ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1966 में आई फिल्म 'सूरज' से की। इसके बाद उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई और फिल्मों में काम किया, जिसमें 'दस लाख' और 'दो कलियां' शामिल हैं। बाल अभिनेत्री के रूप में उनकी 'दो कलियां' फिल्म सबसे लोकप्रिय रही। इसमें उनके डबल रोल को काफी पसंद किया गया और उन्हें खूब सराहना मिली। इसके बाद नीतू ने एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म 'रिक्शावाला' से इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद अभिनेत्री ने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का परिचय दिया, जिसमें 'कभी-कभी', 'यादों की बारात', 'दीवार', 'खेल खेल में', 'काला पत्थर', 'अमर अकबर एंथनी', 'रफू चक्कर', 'दूसरा आदमी', आदि फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के बदौलत वह 70 के दशक की सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। अभिनेत्री ने 22 जनवरी 1980 को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर से शादी की। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के नए अध्याय और परिवार पर ध्यान देने के लिए फिल्मों से लंबे समय का ब्रेक लिया। अभिनेत्री ने शादी के 26 वर्ष बाद एक बार फिर पर्दे पर 'लव आज कल' फिल्म से शानदार वापसी की और 'दो दूनी चार,' 'जब तक है जान,' 'जुग जुग जियो,' और 'बेशरम' जैसी फिल्मों में नजर आईं। दर्शकों को पर्दे पर नीतू कपूर और ऋषि कपूर की जोड़ी काफी पसंद आती थी। नीतू सिंह ने अपने प्रेमी और फिर पति ऋषि कपूर के साथ लगभग 12 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें 'खेल खेल में', 'रफू चक्कर', 'कभी कभी', 'अमर अकबर एंथोनी', 'दूसरा आदमी', 'दुनिया मेरी जेब में', 'जहरीला इंसान', 'पति पत्नी और वो', 'जिंदा दिल', 'अनजाने में', 'झूठा कहीं का' और 'धन दौलत' शामिल हैं। नीतू सिंह ने अपने पूरे करियर में लगभग 80 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनके दो बच्चे हैं, अभिनेता रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी एक फैशन और ज्वैलरी डिजाइनर हैं। वहीं, बेटा रणबीर कपूर बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। रिद्धिमा के पति का नाम भरत साहनी है, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और दोनों की एक बेटी समारा है। वहीं, रणबीर ने अभिनेत्री आलिया भट्ट से शादी की है और उनकी भी एक बेटी राहा है।

मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया : कांग्रेस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार पर देश की शिक्षा व्यवस्था को 'आईसीयू' में पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि इस स्थिति में सुधार के लिए उनकी पार्टी द्वारा जल्द ही एक ''एजुकेशन चार्टर'' तैयार किया जाएगा।कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और पेपर लीक माफिया से उनके कथित संबंधों की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को मोदी सरकार ने आईसीयू में पहुंचा दिया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर के छात्रों से मिल रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सके। उनका कहना था कि इसी उद्देश्य से राहुल गांधी ने हाल में राजस्थान के कोटा में छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच एक प्रस्तुति दी थी और अब इस अभियान को देश के विभिन्न हिस्सों में आगे बढ़ाया जा रहा है।

कन्हैया कुमार ने सरकार के सामने कांग्रेस की तीन मांगे भी रखी।1. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और पेपर लीक माफिया से इनके संबंधों की जांच की जाए2. हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए, जिसके लिए यूपीए सरकार ने कमेटी बनाई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने मनमाने तरीके से एनटीए को खड़ा कर दिया3. युवाओं के लिए नियमित जॉब कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षा भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक एकेडमिक कैलेंडर निकाला जाए। कुमार ने कहा, ''हम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सुझावों को संकलित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम एक एजुकेशन चार्टर बनाएंगे और देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे।''उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए समिति बनाई थी, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने मनमाने तरीके से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का गठन कर दिया। कुमार ने युवाओं के लिए नियमित रोजगार कैलेंडर जारी करने तथा परीक्षाओं और भर्तियों के लिए एक अकादमिक कैलेंडर लागू करने की भी मांग की।इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और शैक्षणिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। जाखड़ ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल बार-बार बढ़ाया जाना सवाल खड़ा करता है। उन्होंने दावा किया कि परिसर में आवाज उठाने वाले छात्रों को मुकदमों की धमकी दी जाती है और विशेष विचारधारा के लोगों की कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने संगठनात्मक चुनावों की शुरुआत की है और वह प्रत्येक परिसर में चुनाव के माध्यम से अपनी इकाइयों का गठन करेगी ताकि छात्रों को अपनी आवाज उठाने का मंच मिल सके।

श्रीभूमि जिले के पांचडाली से श्यामनगर एनडी बांध को जोड़ने वाली सड़क कि क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि। असम के श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के दरगारबंद ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-5 में पांचडाली से श्यामनगर एनडी बांध को जोड़ने वाली सड़क पर वर्ष 2025 में सरकारी पहल से एक पुलिया का निर्माण कराया गया था। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के एक वर्ष के भीतर ही नदी के तेज बहाव के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। वर्तमान में ग्रामीणों के आवागमन का एकमात्र सहारा बांस से बना अस्थायी पुल है, जिसे पार करते समय प्रतिदिन जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया की शीघ्र मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण होने से अनीपुर तक का महत्वपूर्ण और छोटा संपर्क मार्ग फिर से चालू हो जाएगा। इससे दुल्लभछड़ा मॉडल विलेज, कृष्णनगर, रूपाग्राम, श्यामनगर और पांचडाली के लोगों को आनीपुर बाजार तक आसान आवागमन की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग एक वैकल्पिक बाईपास सड़क के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे लंबे समय से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विजय मालाकार से ईस मामले का संज्ञान लेकर घटनास्थल का निरीक्षण कराने, आवश्यक जांच करवाने तथा पुलिया की शीघ्र मरम्मत या पुनर्निर्माण कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। ताकि लोगों का समस्या का समाधान हो सके।

कर्नाटक एसआईआर: अब एनडीए भी लगा रहा है धांधली का आरोप, डीके और सुरजेवाला का पलटवार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एनडीए नेताओं ने इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एनडीए नेताओं को बिहार और बंगाल के एसआईआर में विपक्ष के आरोपों को याद दिलाया है। सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) वी. अनबुकुमार से मुलाकात की और एक औपचारिक शिकायत सौंपी। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के संशोधन में जुटे अधिकारी स्वीकृत नियमों और दिशानिर्देशों की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को घर-घर जाकर सत्यापन करने का सख्त निर्देश है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन नहीं किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि घर घर जाने के बजाय समुदाय भवनों, मस्जिदों और बीएलओ के निजी आवासों पर मतदाता फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके लिए बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को इन जगहों पर आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो कि निर्वाचन आयोग के नियमों का सीधा उल्लंघन है। विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह इन सामूहिक नामांकन शिविरों के जरिए 'अवैध प्रवासियों (जैसे बांग्लादेशी प्रवासियों)' के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का काम कर रही है। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया की तुरंत जांच कराई जाए, अब तक भरे गए सभी फॉर्म का दोबारा घर-घर जाकर अनिवार्य रूप से सत्यापन हो और दोषी अधिकारियों व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एनडीए नेताओं को एक्स पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा- कर्नाटक में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) का विरोध करने वाले कर्नाटक के पूरी तरह से बंटे हुए और निराश BJP नेताओं (जिनके साथ निश्चित रूप से एचडी कुमारस्वामी भी शामिल हैं) का अजीब पाखंड। हम, कांग्रेस और कर्नाटक कांग्रेस के लोग, SIR के प्रति उनके विरोध का स्वागत करते हैं और कर्नाटक के BJP और JD-S नेताओं को चुनौती देते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रही है। शिवकुमार ने कहा, 'सरकार इस प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है और विपक्ष इसी बात से घबराया हुआ है।

राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। राम मंदिर में दान चोरी मामले पर छिड़े विवाद के बीच सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की गई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने पत्रकारों से बातचीत में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''हमने न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हवारे (श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष) की तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की। यह समिति उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी और हमें चुनने के लिए तीन नाम देगी।'' गोविंद देव गिरि ने सोमवार को अयोध्या में ट्रस्ट की एक मैराथन बैठक के बाद कहा, ''यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि अनुभवी लोगों की एक समिति करेगी।'' ट्रस्ट की बैठक से पहले, विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट के मामलों के प्रबंधन के लिए एक सीईओ का पक्ष लिया था और उम्मीद जताई थी कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को हुई करीब तीन घंटे लंबी आपात बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। ट्रस्ट ने चंपत राय की जगह ट्रस्टी कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने चोरी की घटना को 'लज्जाजनक' बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक ट्रस्ट कोई ढिलाई नहीं बरतेगा और पूरे मामले की निगरानी के लिए एक समिति भी गठित की गई है। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना पूरे ट्रस्ट और रामभक्तों के लिए अत्यंत पीड़ादायक और लज्जाजनक है। उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ट्रस्ट ने एक छोटी समिति गठित की है। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश जी हवारे शामिल हैं, जिन्होंने 10 साल तक शिरडी संस्थान का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया था। गोविंद देव गिरी ने कहा कि हमने इस तीन सदस्यीय समिति को अंतिम रूप दे दिया है, वे अलग-अलग उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे और हमें नाम सौंपेंगे, जिनमें से हम अंतिम चयन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर निर्णय लिया जाएगा। गोविंद देव गिरी ने दोहराया कि 'चोरी, चोरी होती है' और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री तक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिन्होंने ट्रस्ट का गठन किया और उसके सदस्यों की नियुक्ति की। योगी सरकार तक, जिसने वर्षों तक इस लूट को जांच के बिना चलते रहने दिया और आरएसएस-वीएचपी माफिया की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करती है यूपी पुलिस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गिरफ्तारी संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी पर पुलिस तंत्र को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की डिवीजन बेंच ने एक नाबालिग को कथित चोरी के मामले में अवैध रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 'सतेंद्र अंतिल बनाम सीबीआई (2022)' और 'अनेश कुमार' जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में गिरफ्तारी को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी कानून पढ़ने, समझने और उसका पालन करने के बजाय अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। कोर्ट ने पाया कि नाबालिग की उम्र की पुष्टि किए बिना उसे जेल भेज दिया गया, जबकि जिन धाराओं में मामला दर्ज था उनमें अधिकतम 3 और 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद BNSS की धारा 35(3) के तहत अनिवार्य नोटिस जारी किए बिना ही गिरफ्तारी कर ली गई।